Issue 1 - JANUARY / जनवरी 2023

कृषक सारथी

Monthly Newsletter of
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED

Sahakar Se Samriddhi -
Prosperity through Cooperatives

People Cooperating People

Production by People

Ease of Doing Business

People before Profit

Ease of Living

People with Purpose

Ease of Cooperation and Access to Opportunities

For Internal Circulation only

माननीय अध्यक्ष का संदेश

प्रिय सहकार बंधुजन,

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि कृभको अपने मासिक समाचार पत्रिका "कृषक सारथी" का पहला अंक ला रहा है।

कृभको ने हमेशा किसानों को अपनी गतिविधियों में अग्रणी रखा है और यह समाचार पत्रिका कृषक समुदाय को इसके और करीब लाएगा। समाचार पत्रिका कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास की दुनिया में हो रहे समकालीन मुद्दों के बारे में शिक्षित करने में किसानों और ग्रामीण समुदाय के बीच जागरूकता फैलाएगा।

मुझे विश्वास है कि इस पहल से जमीनी स्तर पर किसानों और सहकारों में सीधा जुड़ाव होगा। माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह समाचार पत्रिका ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सहकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और आकर्षित करेगा। यह समाचार पत्रिका सहकारिता मंत्रालय की नीतियों पर भी प्रकाश डालेगा।

मैं कृभको समाचार पत्रिका की उज्ज्वल और उपयोगी यात्रा की कामना करता हूं।

सभी पाठकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

डॉ। चंद्र पाल सिंह

Dear Cooperators',

It is moment of pride for KRIBHCO to bring out its maiden volume of Monthly Newsletter. The newsletter will go a long way in amplifying the reach of KRIBHCO to the farming community & Cooperators across geographies.

Taking forward, Hon'ble PM's vision of "Sahakar Se Samriddhi", Hon'ble Minister of Home Affairs and Cooperation, Sh. Amit Shah has set the tone for all the cooperatives. This magazine will surely work to educate and inform farmers about latest happenings in the world of agriculture, Cooperation, Rural Development and other allied sectors.

Newsletter will spread the message of cooperation far and wide and would be an effective tool to inspire and attract rural youth and women to join with cooperative movement.

I would convey my best wishes for a bright and fruitful journey of the KRIBHCO newsletter in times to come.

My best wishes to the editorial team of KRIBHCO newsletter.

Rajan Chowdhry
Managing Director

MD's Message

Memorandum of Understanding signed to facilitate low interest rate loans to farmers

Produce Marketing Loan features nil processing fee, No Additional collateral and attractive interest rates to facilitate farmers in providing low interest rate loans, Warehousing Development Regulatory Authority (WDRA) signed Memorandum of Understanding (MoU) with a nationalized bank in an event.

The MoU was signed with the intent of promoting awareness about the new loan product called Produce Marketing Loan to exclusively fund against e-NWRs (electronic Negotiable Warehouse Receipt) with features such as Nil processing fee, No Additional collateral and attractive interest rates.

Combined with the inherent security and negotiability of the e-NWR system, the Produce Marketing Loan will go long way in improving rural liquidity and increasing farmers' income. The MoU was signed with the State Bank of India (SBI).

Source: PIB Delhi

International Year of Millets (IYM) 2023 kick starts with Focused Activities being undertaken by Central Ministries, State Governments and Indian Embassies

Spearheaded by the Prime Minister, the Government of India sponsored the proposal for International Year of Millets (IYM) 2023 which was accepted by the United Nations General Assembly (UNGA).

DA&FW aims to promote cultivation and consumption of Millets at a larger scale and bring it to the entire globe through IYM.

Central ministries, states and Indian embassies allocated a focused month in 2023 to carry out various activities for promotion of IYM and increase awareness about benefits of millets.

January 2023 is the focused month for the Ministry of Sports and Youth Affairs, Government of India and States of Chhattisgarh, Mizoram and Rajasthan for conducting events / activities for IYM.

Source: PIB Delhi

India's December NP/NPK sales, imports, output all up

NP/NPK sales under India's direct benefit transfer (DBT) system rose year on year last month, as did imports and domestic production. December sales were up by 9.5% on the year at 1.04mn t, while production increased by 63% to about 858,000 MT. Imports climbed by 31% year on year to 143,000MT last month. Government statistics imply NP/NPK stock levels in India of about 2.64mn t at the end of December, down by 1.5% from a month earlier but up by 39% on the year.

Domestic production of NP/NPKs in India rose by 4% to about 7.08mn t in April-December, but DBT sales fell by 16% to 8.04mn t.

Source: Argus Direct

Reports being circulated on social media regarding adulteration in milk adversely affecting the health of public in the country is false and contrary to facts

It has come to the notice of Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying that a media report about a WHO advisory to the Government of India allegedly states that, if adulteration of milk and milk products is not checked immediately, 87% of citizen would be suffering from serious disease like cancer by the year 2025. Dissemination of this kind of false information is creating unnecessary panic among the consumers

In this regard, the Department has informed that this matter has already been examined in the Department in consultation with Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). WHO country office in India confirmed to FSSAI that no such advisory has been issued by WHO to Government of India ever.

The Department has reiterated that this kind of false information being circulated in the social media and on WhatsApp should not be given any credence whatsoever. Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), Government of India and FSSAI are taking all possible steps to help supply of safe and good quality milk to the consumers across the country

Source: PIB Delhi

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को मंजूरी दी

इसे बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया जाएगा

पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं। उपनियमों के अनुसार, इन सभी सहकारी समितियों के समिति बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे

यह प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों के समर्थन से देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित अधिशेष वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए एक व्यापक (अम्ब्रेला) संगठन के रूप में कार्य करेगी

सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समर्थन से एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना और इसके संवर्धन को मंजूरी दे दी है। प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालय, 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' का पालन करते हुए अपनी निर्यात संबंधी नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात के लिए प्रस्तावित समिति को समर्थन प्रदान करेंगे।

प्रस्तावित समिति निर्यात करने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक (अम्ब्रेला) संगठन के रूप में कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र से निर्यात पर जोर देगी। इससे वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को गति देने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित समिति 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के माध्यम से सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी, जहां सदस्य, एक ओर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर वे समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश द्वारा भी लाभान्वित होंगे।

प्रस्तावित समिति के माध्यम से होने वाले उच्च निर्यात के कारण सहकारी समितियां, विभिन्न स्तरों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगी, जिससे सहकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। वस्तुओं के प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं को बेहतर बनाने से भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहन देगी, जिससे अंततः आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना को मंजूरी दी

पैक्स से एपेक्स : प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं। इसके उपनियमों के अनुसार, सोसायटी के बोर्ड में इन सभी सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण; महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास; और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) और किस्म प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) को बढ़ावा देगी और उपज अंतराल को कम करने एवं उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी।

सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना करने और उसे प्रोत्साहन देने के एक ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) की सहायता और उनकी योजनाओं व एजेंसियों के जरिए देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से 'सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण; महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास; और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

पैक्स से एपेक्स : प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इसकी सदस्य बन सकती हैं। इसके उपनियमों के अनुसार, सोसायटी के बोर्ड में इन सभी सहकारी समितियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि सहकारी समितियों की ताकत का लाभ उठाने के हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सफल और ऊर्जावान व्यावसायिक उद्यमों में बदला जाना चाहिए, क्योंकि सहकारी समितियों के पास देश के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी मौजूद है।

राष्ट्रीय स्तर की यह बहु राज्य समिति संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) की सहायता और उनकी योजनाओं व एजेंसियों के जरिए देश भर की विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण; महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास; और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी।

प्रस्तावित समिति सभी स्तरों की सहकारी समितियों के नेटवर्क का उपयोग करके बीज प्रतिस्थापन दर, किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज किस्म के परीक्षणों में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करने, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में मदद करेगी। गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा किसानों की आय में भी वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इसके सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन से बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों के उच्च उत्पादन और समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश, दोनों से लाभ होगा।

बीज सहकारी समिति गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज किस्म के परीक्षणों, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करके एसआरआर, वीआरआर को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के सहकारी ढांचों और अन्य सभी साधनों को शामिल करेगी।

राष्ट्रीय स्तर की इस बीज सहकारी समिति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे कृषि और सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा; आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को स्वीकृति दी

इसे बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा

पैक्स से एपेक्स : प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ, बहु राज्य सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इन सभी सहकारी समितियों के उपनियमों के अनुसार सोसायटी के बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे

यह प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों के समर्थन से जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणीकरण, जांच, ब्रांडिंग और विपणन के रूप में कार्य करेगी

सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एम/डोनर) की नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से 'संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण' के समर्थन के साथ बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति को स्थापित करने और बढ़ावा देने के एक ऐतिहासिक निर्णय को स्वीकृति दे दी है।

इसलिए, जैविक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करके सहकारी क्षेत्र से जैविक उत्पादों पर जोर देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की आवश्यकता महसूस की गई है।

पैक्स से एपेक्स: प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ, बहु राज्य सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। इन सभी सहकारी समितियों के उपनियमों के अनुसार सोसायटी के बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे।

सहकारी समिति प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पाद उपलब्ध कराकर जैविक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेगी। यह घरेलू के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत क्षमता को जानने में मदद करेगी। यह सोसायटी सहकारी समितियों और अंततः उनके किसान सदस्यों को सस्ती कीमत पर जांच व प्रमाणन की सुविधा देकर व्यापक स्तर पर एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पादों के उच्च मूल्य का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी।

सहकारी समिति प्राथमिक कृषि ऋण सहित सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को एकत्रीकरण, प्रमाणन, जांच, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रसद सुविधाओं, जैविक उत्पादों के विपणन और वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिए संस्थागत मदद भी प्रदान करेगी। सोसायटी/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से सभी जैविक उत्पादों के प्रचार व विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदारी करेंगे। यह उन मान्यता प्राप्त जैविक परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों को सूचीबद्ध करेगी, जो परीक्षण और प्रमाणन की लागत को कम करने के लिए समाज द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि सहकारी समितियों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें सहकार-से-समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सफल और प्रेरक व्यावसायिक उद्यमों में बदलना चाहिए। इस प्रकार सहकारी समितियों के लिए वैश्विक स्तर पर विचार करना और इसका तुलनात्मक लाभ उठाने के लिए स्थानीय रूप से कार्य करना अनिवार्य है।

Drones in Agriculture

The necessity of increasing food production to meet the demand of the ever-increasing population in India needs no emphasis. Estimates suggest that at current level production, and additional 5 Mt food grain has to be added each year to national food basket for next decade to fed the increasing population. Agriculture sector is still far behind in technological advancements and usage of advance technologies. Major activities of farming are labour intensive and time consuming.

Drones have the ability to move around at desired pace and in the targeted spatial dimensions. Drones can be completely controlled from a distant location. They can carry different types of materials including agricultural inputs. These features of drones make them highly suitable for agricultural use. Use of advance technology like drones will really aid the farming community in reducing the use of labour, time as well cost of activities involved in agriculture. Drones are capable of performing simple as well as precise actions for crop cultivation and livestock rearing. Drones can be utilized in many ways to reduce overall cost and improve the productivity of the farm. Some of the applications of drones in agriculture is discussed below:-

Field soil analysis and monitoring the soil health

Surveys of field soils with the use drones can help in analysing the field conditions for planting, irrigation and nutrient level management. Periodic use of drones can be useful in monitoring the health of soil during the cropping season as well as when the field remained empty. The fertility levels of soils can be ascertained with the help of sensors mounted on drones.

Monitoring and surveillance of crop health

Crop health surveillance is the supervision of crop progress from seeds sowing till the crop is harvested. Monitoring the health of vegetation is crucial to detect bacterial/fungal infections at an early stage. With infrared mapping the drones can collect the light reflected by leaves of plants. The collected data helps to produce multispectral images to track vegetation health. Regular monitoring and early discoveries of any defects can help save crops from damages.

Monitor growth, examine flaws and damage assessment

Vegetation growth determines the output levels of the crop and to ensure better harvest availability as per market requirement the crop needs to be surveyed and monitored. It is also important for determining the right price for the harvest in the market, or harvesting cyclical crops. Drones can collect data on regular intervals and provide accurate information about stages of crop growth, and report any variations. Multispectral images can show subtle differences between healthy and unhealthy crops. Drones can be used to map the flaws in real-time, and the information can be utilized to make additional crop decisions. The drones mounted with multispectral sensors and RGB sensors can detect field areas inflicted by infections, pests and weeds. Based on the collected data the amounts of chemicals needed to fight these infestations, pests and weeds are calculated which reduce the cost of cultivation.

Seeding and planting

Agriculture by design is labour-intensive and time-consuming. Seeding, planting and application of nutrients to soil consumes labour and time. Drone are being used to shoot pods, their seeds, and crucial nutrients into the soil. It reduces costs, labour, fuel and increases consistency & efficiency. The attachments like lasers, sensors, tanks etc. for drones enable them to plant seeds swiftly and cleanly.

Spraying of fertilizers, insecticides and other agro chemicals

Crops require application of fertilizers, insecticides, pesticides and other agro chemicals based on conditions of field and vegetation. The application of these chemicals in general needs intensive use of labour, time and fuel. Use of drones have helped to simplify the time-consuming process of agricultural fertilization and application of agro chemicals. Human contact with such harmful chemicals is reduced and Agri-drones can carry out such tasks much quicker. Drones having RGB sensors and multispectral sensors can precisely detect and treat problematic areas.

Monitoring of water requirement and irrigation

Large scale farming has huge requirement of water and efficient irrigation system. Drones, including hyperspectral, thermal, or multispectral sensors can recognize the areas that are dry or need irrigation. Monitoring of irrigation disclose potential pooling/leaks, reduces cost improve water use efficiency. Timely application of irrigation helps in better vegetation growth and increased levels of crop yields.

Tracking of livestock

Rearing of livestock is deeply integrated with agriculture. Tracking of livestock is one of the major concerns of farmers. Drone survey allows the farmers to keep track and monitor the movements of their cattle. Use of thermal sensor technology helps to find lost animals and detect an injury. Drones can carry out such functions round the clock which sets farmers free for other important tasks. Use of drones in increasing in dairy technology.

Agricultural drone technology is the future of the farming community. Though this technology is little complex in the present form, very soon the simplified versions will be ubiquitous. Drones can change the way farming is being done through conventional methods. There are some limitations of this technology as well like Connectivity issue, Weather dependent operations, requirement of Knowledge & Skill for operations. These limitations will reduce to greater extent if the adoption of technology is at large scale and improvement in technology continues. The benefits of using drones in agriculture outweighs the limitations and we must endeavour to help everyone in adoption of this futuristic technology.

Dayanand Kumar, DM (Mktg), CMO, NOIDA

कृभको ने नया उत्पाद, सिवारिका, समुद्री शैवाल जैव–वर्धक पेश किया

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) भारत की अग्रणी उर्वरक उत्पादक सहकारी समिति है। इस समिति का विशाल उर्वरक उत्पादन संयंत्र हजीरा, सूरत में स्थित है। यह समिति अपनी नवीनतम उत्पाद श्रृंखला के साथ किसानों की सेवा करने में सदैव अग्रणी रहती है।

कृभको ने 26.12.2022 को एक और नवीनतम टिकाऊ उत्पाद, सिवारिका लॉन्च किया है। यह उत्पाद समुद्री शैवाल जैव–वर्धक है। सिवारिका के दानों को लाल और भूरे रंग के शैवाल से समुद्री शैवाल अर्क निकालकर प्रतिपादित किया जाता है। सिवारिका समुद्री शैवाल प्रौद्योगिकी के प्रदाता सीएसआईआर–सीएसएमसीआरआई हैं। सिवारिका, समुद्री शैवाल एक मेटाबोलिक जैववर्धक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण और अन्य निहित पोषक तत्व, विटामिन, पौधे के विकास हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जिबरलिन, बीटाइन और मैनिटोल आदि होते हैं।

इस उत्पाद की खेती और उपज भारतीय तट से की जाती है और यह कई मछुआरा परिवारों की आजीविका का स्रोत है।

इस उत्पाद को श्री राजन चौधरी, प्रबंध निदेशक, कृभको द्वारा कृभको भवन, नोएडा में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर निदेशक (मानव संसाधन), विपणन निदेशक, वित्त निदेशक, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण और बिजनेस पार्टनर मेसर्स पुष्पा जे. शाह के निदेशक उपस्थित थे।

इस अवसर पर, कृभको के प्रबंध निदेशक ने कहा कि यह किसान अनुकूल उत्पाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाएगा, अधिक उपज प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा और यह मिट्टी स्वास्थ्य सुधार करने में भी सहायता करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृभको किसानों की जरूरतों को पूरा करने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आजीविका में सुधार लाने का काम जारी रखेगी।

KRIBHCO in Snapshots

Delegation from Kazakhstan led by Mr. Kazybek Shaikh, President of the National Association of Cooperatives visited KRIBHCO on 21.12.2022.

Delegation from Jordan led by Mr. Abdel Fattah M.Q. – Shalabi, Director General, Jordan Cooperative Corporation visited KRIBHCO on 11.01.2023 and had an interacting sessions with Dr. Chandra Pal Singh, Chairman and other senior officials of KRIBHCO on the topics of mutual interest.

Dr. VK Tiwari, DGM (Mktg) receiving the Second Prize for in-house Journal "KRIBHCO News" at PRSI Annual Awards 2022 from Sh. Vishvas Sarang, Minister of Medical Education, Bhopal Gas Tragedy Relief & Rehabilitation, Govt. of Madhya Pradesh.

Social Media Campaigns by KRIBHCO

The importance and role of social media in life is increasing at a warp speed. From connecting with friends to getting the updates of the world, social media is one of the powerful tool to engage and communicate with desired users sitting at one place. Cooperatives which are known for their grass-root level connection and transparency, till date, have not been able to realise the potential of the social media to its fullest unlike private contemporaries. This is not only hindering the potential outreach of cooperative movement but also the business advantages that it offers

Of late, after the formation of Ministry of Cooperation by Government of India; realising the benefits that social media offers, a special emphasis is being made on the usage of various digital platforms by all the national cooperatives. The objective is not just to enhance the business, but to increase the awareness of the cooperatives along with their policies and offerings.

KRIBHCO, being a leading national cooperative, believes that social media platforms are the new age communication tools wherein its members and customers freely interact with the society even from the remotest corner of the country. Though our social media campaign started by the end of 2020, it only caught momentum in second leg of 2022. Today, we are integrating social media campaign with our traditional campaigns, wherein rural population is advocated on the social media benefits and its impact. As on date, KRIBHCO is active on Twitter, YouTube, Facebook, Instagram and Koo, wherein content is posted everyday on variety of topics like product, policy, educational, agriculture etc.

KRIBHCO is sure that, with the usage of social media platforms in the times to come, cooperatives will make a larger impact in the hearts of the people and contribute immensely towards our growing economy.

Facebook | Instagram | Koo | Twitter | YouTube

KRIBHCO in News

कृभको की उर्वरक संवर्धन संगोष्ठी आयोजित

कृषक दूत भोपाल 17 से 23 जनवरी 2023 आंचलिक

कृभको ने स्वच्छता सामग्री की वितरित

KRIBHCO launches new product, SIVARIKA, Seaweed bio-stimulant

Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO) is one of the pioneer fertilizer organization of India having its manufacturing unit at Hazira, Surat. KRIBHCO is always at forefront to serve farmers with its innovative product line. The product was launched by RajanChowdhry, MD, KRIBHCO and it was attended by Director HR, Marketing Director, Finance Director, other senior officials and business partner M/s Pushpa J. Sh... ...rs at KRIBHCO Bhawan, Noida. On this occ... ..., this farmer friendly ... facilitate in achieving ... soil health. He also ... work towards full ... livelihood directly or

किसानों को सभा में बताई शासन की योजनाएं

15 : जनवरी 2023 : रविवार

देवास : शहर एवं जिले की प्रमुख खबरें

कृभको देवास द्वारा ग्राम - सेकली विकासखंड टोंकखुर्द में संध्या कालीन किसान सभा का आयोजन किया गया

देवास : पंडित रघुनंदन समाधिया

कृभको ने लॉन्च किया सिवारिका

कृषि गोल्डलाइन, नई दिल्ली। कृभको ने विगत दिनों एक और नवीनतम टिकाऊ उत्पाद, सिवारिका लॉन्च किया है। यह उत्पाद समुद्री शैवाल जैव-वर्धक है। सिवारिका के दानों को लाल और भूरे रंग के सिवारिका समुद्री शैवाल का अर्क निकालकर ...

Designed by Wide Reach Advertising

कृषक भारती कोओपरेटिव लिमिटेड
KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED
कृभको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा - 201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)
KRIBHCO Bhawan, A-10, Sector-1, NOIDA - 201301, District Gautam Budh Nagar (U.P.)